

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2021 (बांसवाड़ा आर्डर)

फतह सिंह पिता किशोर सिंह, जाति राजपूत, निवासी टामटिया, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. चन्द्रवीर सिंह पिता दलपत सिंह, जाति राजपूत, निवासी टामटिया, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत नियम-17 राजस्थान उपनिवेशन
(माही परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं
विक्रय) नियम 1984 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा दिनांक 11.09.2019 प्रकरण सं0 2/2011
---/---

- उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्त
2. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट सं0 2

---:---
निर्णय

दिनांक 20-02-2024



प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्त ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम 1984 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टामटिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा में खसरा नंबर 489 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर दिनांक 20-0-1985 को अपने नाम आवंटित करवा ली, जबकि उक्त आराजी के 3 बीघा पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होकर आज भी मौजूद है, जिससे लगती हुई प्रार्थी की पैतृक खातेदारी की आराजी नंबर 484/2 रकबा 2 बीघा स्थित है। अप्रार्थी आवंटन दिनांक को नाबालिग था एवं कानूनन नाबालिग के पक्ष में आवंटन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अप्रार्थी के पिता ने कानून की अवहेलना करते हुए मिलीभगत से आवंटन करवा लिया है। आवंटन पर पर्याप्त सदस्यों के



00
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हस्ताक्षर नहीं है तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी है। अतः उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे विधिवत आवंटन किया गया है तथा आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के कारण उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

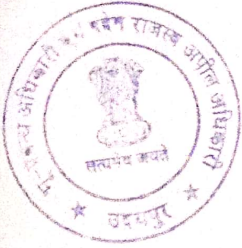
अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 11-09-2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19-03-2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को सम्मन नोटिस जारी कर तलब किये जाने पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्त ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्त अस्वस्थ होने, ज्ञान एवं शिक्षा की कमी होने तथा सीनियर सिटीजन होने व कोविड-19 की महामारी के कारण अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा बताया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया है। वक्त आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नाबालिग था, कानूनन नाबालिग के पक्ष में किसी प्रकार आवंटन किया ही नहीं जा सकता। आवंटन पश्चात आवंटन द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। कब्जा आज भी अपीलान्त का ही चला आ रहा है, लेकिन अधिनस्थ



(Handwritten Signature)
 जिला न्यायाधीश
 एवं पदेन राजस्व बराल अधिकारी
 उदयपुर (राज.)


न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त करते हुए रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्त की यह आपत्ति की वक्त आवंटन रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 1 नाबालिग था, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, कब्जे बाबत् भी कोई प्रमाणन नहीं है तथा यदि अपीलान्त का कब्जा मान भी लिया जावे तो वह बतौर अतिकमी है तथा अतिकमी का कोई लोकस स्टैण्डर्ड भी नहीं होता। आवंटन वर्ष 1985 में हुआ है, जबकि अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया, जो करीब 26 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्त का यह कथन कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है, जबकि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों पालना किये जाने के कारण ही उसे खातेदार अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। तदनुसार हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की जाना हम नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11-09-2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दपतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20-02-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (प्रदीपसिंह सांगावत)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी
 एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर